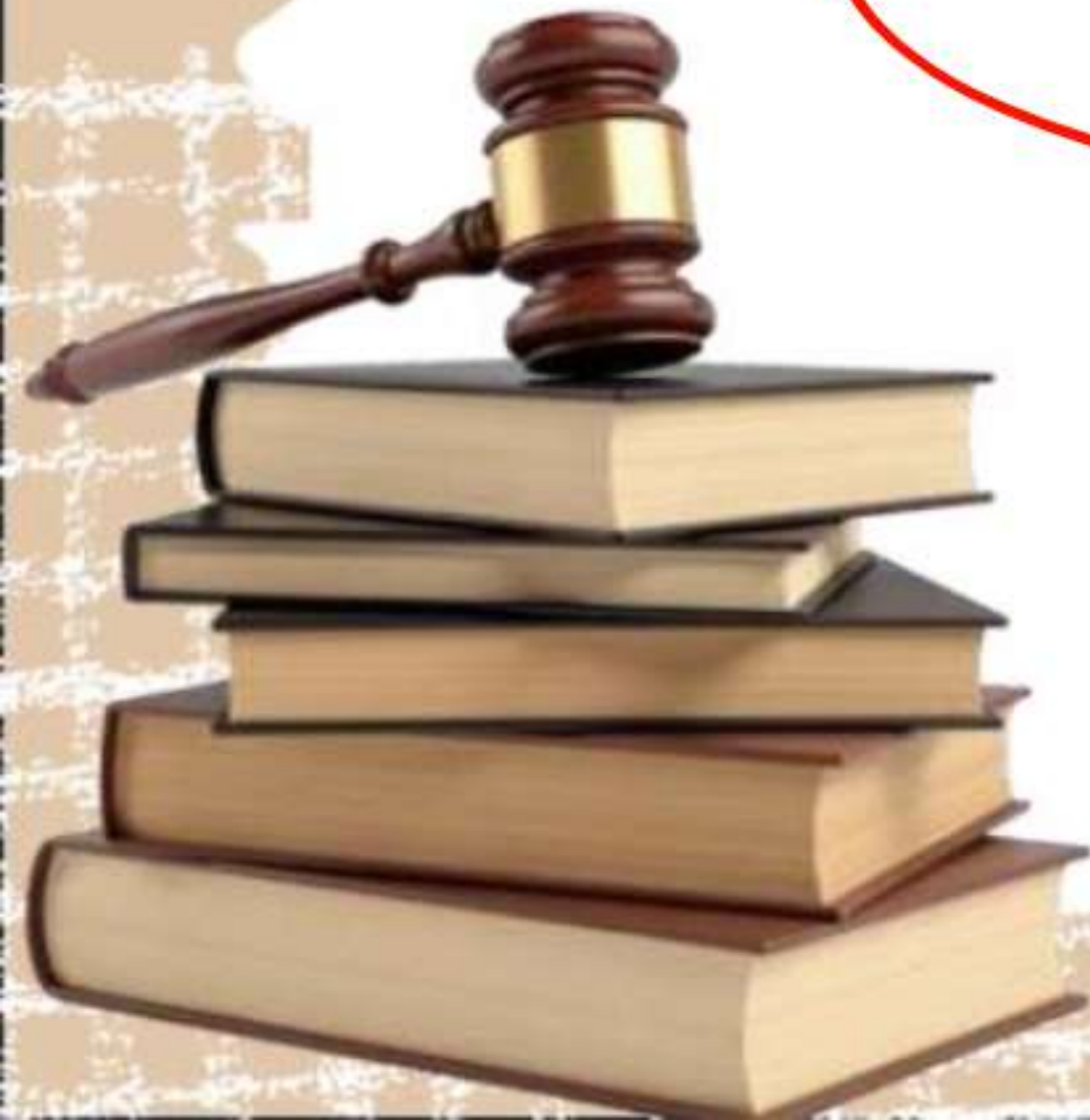


Not in Constitution

Non Constitutional Bodies

गैर-संवैधानिक निकाय



Planning Commission

Sys.

NITI Aayog (National Institution for Transforming India)

- NITI Aayog is a policy think tank of the Government of India./ नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है।
- It was established to replace the Planning Commission in 2015./ इसे 2015 में योजना आयोग की जगह लेने के लिए बनाया गया था।
- It aims to promote cooperative and competitive federalism by involving the states in policy-making./ इसका मकसद राज्यों को पॉलिसी बनाने में शामिल करके कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज़्म को बढ़ावा देना है।
- It is headquartered in New Delhi./ इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।



Composition संघटन

- **Chairperson** : Prime Minister of India/ भारत के प्रधानमंत्री
- **Vice – Chairperson** : Appointed by the Prime Minister/ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **Full time Members** : Experts from various fields/ पूर्णकालिक सदस्य: विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ
- **Ex-officio members** : 4 Union Ministers / पदेन सदस्य: 4 केंद्रीय मंत्री
- **Chief Executive Officer (CEO)**: Appointed by the Prime Minister/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **Governing Council** : Chief Minister of all States and Union Territories with legislature, and Lt. Governors of other UTs./
गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।



नीति आयोग

Objectives

P/C → Top → Bottom

- Foster cooperative federalism between the centre and states./ केंद्र और राज्यों के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म को बढ़ावा देना।
- Design and implement strategic and long-term policies./ स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग-टर्म पॉलिसी बनाना और लागू करना।
- Promote innovation, entrepreneurship and sustainable development./ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
- Encourage bottom-up planning (from village to national level)./ बॉटम-अप प्लानिंग (गांव से लेकर नेशनल लेवल तक) को बढ़ावा देना।
- Serve as a knowledge and innovation hub for policy formulation./ पॉलिसी बनाने के लिए नॉलेज और इनोवेशन हब के तौर पर काम करना।

Major Initiatives / मुख्य पहलें :

- Aspirational Districts Programme/ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम
- Atal Innovation Mission / अटल इनोवेशन मिशन (AIM)
- Digital India Initiatives/ डिजिटल इंडिया पहल ✓
- Sustainable Development Goals Index/ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स
- India@75 vision ✓
- Composite water management Index/ कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स



National Human Rights Commission (NHRC)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- The NHRC is a statutory body established to protect and promote human rights in India. / NHRC भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है।



Establishment

- Established on : 12 October 1993
- Under : Protection of Human Rights Act, 1993 / मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- Type : Statutory body / वैधानिक निकाय
- Headquarter : New Delhi



Recent Chairperson :
Justice V. Ramasubramanian

NHRC Members

1 + 5 + 7

Chairman
(Retired CJ
or retired judge
of
S/C)

full time members

②
Retired
Judges
of
High Court

③
Must have
Advance
Knowledge of
Human Rights
(Must be one
Woman)

Ex-officio Members

- ① - National Commission of SC → Chairman
- ② - " " ST → "
- ③ - " " BC → "
- ④ - " " Women → "
- ⑤ - " Rights for Children → "
- ⑥ - " Person of Disability → "
- ⑦ - " Minorities → "

Composition / संघटन

- **Chairperson** : Retired Chief Justice of India/ भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस
- **Members** : One serving or retired judge of the Supreme court – one serving or retired chief justice of a High court – two persons having knowledge of human rights / सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या रिटायर्ड जज – हाई कोर्ट के एक सेवारत या रिटायर्ड चीफ जस्टिस – मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाले दो व्यक्ति (5 Full Time Members + 7 Ex- Officio Members)
- **Ex-officio members** : chairpersons of / पदेन सदस्य: निम्नलिखित के चेयरपर्सन:
 - ✓ National Commission for SCs/ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
 - ✓ National Commission for STs/ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 - ✓ National commission for women/ राष्ट्रीय महिला आयोग
 - ✓ National commission for minorities/ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- **Appointed by** : President of India/ भारत के राष्ट्रपति द्वारा
- ✓ **Tenure** : 3 years or up to 70 years of age (whichever is earlier/ जो भी पहले हो)

Functions :

- **Inquire into complaints of human rights violations by public servants./** सरकारी कर्मचारियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना।
- **Visit jails and detention centers to study living conditions of inmates./** कैदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों और डिटेन्शन सेंटर्स का दौरा करना।
- **Review constitutional and legal safeguards for human rights./** मानवाधिकारों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
- **Recommend measures for effective implementation of human rights laws./** मानवाधिकार कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों की सिफारिश करना।
- **Promote research and awareness about human rights./** मानवाधिकारों के बारे में रिसर्च और जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **Encourage NGOs and institutions working in this field/** इस क्षेत्र में काम करने वाले NGO और संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

Powers :

- **can summon witness, demand documents, and conduct investigations.** / गवाहों को बुला सकता है, दस्तावेज़ मांग सकता है, और जांच कर सकता है।
- **Has powers similar to a civil court under the code of civil procedure.** / सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक सिविल कोर्ट के समान अधिकार हैं।
- **However, NHRC can only recommend – it cannot enforce its decisions.** / हालांकि, NHRC केवल सिफारिश कर सकता है - यह अपने फैसलों को लागू नहीं कर सकता।



National Commission for Women

- The National Commission for Women (NCW) is a statutory body established to safeguard the rights and interests of women and to advise the government on all policy matters affecting women./
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन (NCW) एक कानूनी संस्था है जिसे महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी पॉलिसी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए बनाया गया है।



Establishment / स्थापना :

- Established on : 31 January 1992
- Under : National Commission for Women Act, 1990.
- Type : statutory body/ कानूनी संस्था
- Headquarter : New Delhi



Recent Chairperson :
Vijaya Kishore Rahatkar

Composition / संघटन

Position / पद	Details / विवरण (Total = 7 Members)
Chairperson / अध्यक्ष ✓	• Nominated by the Central Government (a woman of outstanding ability and integrity) / केंद्र सरकार द्वारा नामित (उत्कृष्ट क्षमता और ईमानदारी वाली महिला)
5 Members / सदस्य	• 5 members nominated by the Central Government from various fields such as law, women's welfare, administration / कानून, महिला कल्याण, प्रशासन आदि विभिन्न क्षेत्रों से 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं
Member Secretary / सदस्य सचिव ↘	• Nominated by the Central Government (an expert or officer experienced in service matters) / केंद्र सरकार द्वारा नामित (सेवा मामलों में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अधिकारी)

Advice

Functions

- **Safeguards the constitutional and legal rights of women.** / महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है।
- **Investigate complaints or violations of women's rights.** / महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन या शिकायतों की जांच करता है।
- **Study gender-related issues and recommend reforms.** / जेंडर से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करता है और सुधारों की सिफारिश करता है।
- **Inspect jails, remand homes, and women's institution.** / जेलों, रिमांड होम और महिलाओं के संस्थानों का निरीक्षण करता है।
- **Review laws and suggest amendments to remove discrimination.** / कानूनों की समीक्षा करता है और भेदभाव को खत्म करने के लिए संशोधन सुझाता है।



National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)

Establishment / स्थापना

- ✓ **Established on :** 5 March 2007
- ✓ **Under :** commission for protection of child rights Act, 2005 / बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- ✓ **Type :** statutory Body / वैधानिक निकाय
- ✓ **Headquarters :** New Delhi



Recent Chairperson :
Priyank Kanoongo

Definition of a Child :
A person below the
age of 18 years

Composition संघटन



Position / पद	Details / विवरण (Total= 7 Members)
Chairperson / अध्यक्ष ✓	A person of eminence with experience in child welfare, appointed by the Central Government / बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है
Members / सदस्य	6 members (at least 2 women) with expertise in health, child education, child psychology, law and child development / 6 सदस्य (कम से कम 2 महिलाएँ) जिन्हें स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, कानून और बाल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता हो
Tenure / कार्यकाल	3 years or until 65 years of age (whichever is earlier) / 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

Functions

- **Examine and review safeguards for child rights under the constitution and laws./** संविधान और कानूनों के तहत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के उपायों की जांच और समीक्षा करें।
- **Inquire into violations of child rights and recommend remedial action/** बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करें और सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करें।
- **Study and promote research in child rights./** बच्चों के अधिकारों पर रिसर्च का अध्ययन करें और उसे बढ़ावा दें।
- **Create awareness and spread child rights literacy./** जागरूकता पैदा करें और बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी फैलाएं।
- **Inspect juvenile homes, orphanages, and child care institutions./** जुवेनाइल होम, अनाथालय और चाइल्ड केयर संस्थानों का निरीक्षण करें।
- **Recommend policy measures to the government./** सरकार को नीतिगत उपायों की सिफारिश करें।



National Commission for Minorities

- The national commission for minorities (NCM) is a statutory body set up to protect the interest of religious and linguistic minorities in India./ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ (NCM) एक कानूनी संस्था है जिसे भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

Establishment / स्थापना :

- Established on : 17 May 1993
- Under : National Commission for Minorities Act, 1992/
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, 1992
- Type : statutory body/ कानूनी संस्था
- Headquarters : New Delhi

Chairperson: Shri Iqbal Singh
Lalpura



Recognized Minorities (by Government of India)

मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक (भारत सरकार द्वारा)

- Muslims ✓
- Christians ✓
- Sikhs ✓
- Buddhist ✓
- Parsis (Zoroastrians) ✓
- Jains (added in 2014) ✓

Composition / संघटन

Position / पद	Details / विवरण
Chairperson / अध्यक्ष ✓	• Nominated by the Central Government / केंद्र सरकार द्वारा नामित
Vice-Chairperson / उपाध्यक्ष ✓	• Nominated by the Central Government / केंद्र सरकार द्वारा नामित
Members / सदस्य	• 5 members nominated by the Central Government / 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं
Tenure / कार्यकाल	• 3 years / 3 वर्ष

6

members

Central Information Commission

- The central Information Commission is a statutory body established under the Rights to Information (RTI) Act, 2005./ केंद्रीय सूचना आयोग एक कानूनी संस्था है जिसे सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।
- Establishment / स्थापना :
- Established on : 12 October 2005
- Under : Right to Information Act, 2005/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- Type : Statutory Body/ वैधानिक निकाय
- Headquarters : New Delhi



Recent Chairperson :
Heeralal Samariya

Composition / संघटन

Position / पद	Details / विवरण
Chief Information Commissioner (CIC) / मुख्य सूचना आयुक्त	Appointed by the President / राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
Information Commissioners / सूचना आयुक्त	Up to 10, appointed by the President / अधिकतम 10, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
Appointing Committee / नियुक्ति समिति	Prime Minister (Chairperson) - Leader of Opposition in Lok Sabha - A Union Cabinet Minister nominated by the PM / प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) - लोकसभा में विपक्ष के नेता - प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री
Tenure / कार्यकाल	3 years or until 65 years of age (whichever is earlier) / 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
Reappointment / पुनर्नियुक्ति	Not eligible for reappointment / पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं

Central Vigilance Commission (CVC)

- The central vigilance commission (CVC) is the apex integrity institution in India./ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) भारत में सबसे बड़ी इंटिग्रिटी संस्था है।
- It is an independent statutory body created to prevent corruption and ensure clean governance in the central government and public sector organization./ यह एक आज़ाद कानूनी संस्था है जिसे केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइज़ेशन में भ्रष्टाचार को रोकने और साफ़-सुथरा शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

Establishment / स्थापना :

- ✓ Established on : 1964 (based on the Santhanam Committee's recommendation/ संधानम समिति की सिफारिश के आधार पर)
- ✓ Statutory status : given by the central vigilance commission Act, 2003/ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, 2003 द्वारा दिया गया
- ✓ Type : statutory body/ कानूनी संस्था
- ✓ Headquarters : New Delhi



Composition / संघटन

Position / पद	Details / विवरण
Central Vigilance Commissioner / केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ✓	• Head of the commission / आयोग के प्रमुख ✓
Vigilance Commissioners / सतर्कता आयुक्त ✓	• 2 commissioners / 2 आयुक्त
Total Members / कुल सदस्य	• 3 (1 Chief + 2 Members) / 3 (1 प्रमुख + 2 सदस्य)
Appointed by / नियुक्त करने वाला	• President of India / भारत के राष्ट्रपति
Appointing Committee / नियुक्ति समिति ✓	• Prime Minister (Chairperson), Home Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha / प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता
Tenure / कार्यकाल ✓	• 4 years or up to 65 years of age (whichever is earlier) / 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

Central Bureau of Investigation (CBI)

- The CBI is the premier investigating agency of India./ CBI भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है।
- It Investigates cases of corruption, economic crimes, serious crimes, and special cases referred by the government or courts./ यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों, गंभीर अपराधों और सरकार या अदालतों द्वारा भेजे गए खास मामलों की जांच करती है।

DoPT

Establishment / स्थापना :

- ✓ Established in / स्थापना : 1963
- ✓ Origin : derived power from the Special Police Establishment (SPE) set up in 1941./ 1941 में स्थापित स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE) से शक्ति प्राप्त की।
- ✓ Headquarters : New Delhi
- ✓ Parent Ministry : Ministry of personnel, public Grievances and Pensions/
मातृ मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- ✓ It functions under the department of Personnel and training (DoPT)/ यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के तहत काम करता है।



Lokpal and Lokayuktas

→ Central Gov

State

- The Lokpal and Lokayuktas are anti-corruption authorities established to inquire into allegations of corruption against public officials./ लोकपाल और लोकायुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए स्थापित भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण हैं।
- They aim to ensure clean governance and strengthen accountability in public administration./ उनका लक्ष्य स्वच्छ शासन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही को मजबूत करना है।

Establishment / स्थापना :

- Under : Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 / लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- Came into force on : 16 January 2014
- Type : statutory body/ वैधानिक निकाय



Law Commission of India

- The law commission of India is an advisory body established by the Government of India to recommend legal reforms and review existing laws to make them just, fair, and effective./ भारत का लॉ कमीशन भारत सरकार द्वारा कानूनी सुधारों की सिफारिश करने और मौजूदा कानूनों की समीक्षा करके उन्हें न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए स्थापित एक सलाहकार संस्था है।

Establishment / स्थापना :

- First established in / पहली बार स्थापित : 1955
- By : Government of India (not a constitutional or statutory body – it's executive in nature)/ भारत सरकार (यह संवैधानिक या वैधानिक संस्था नहीं है - यह कार्यकारी प्रकृति की है)
- Type : non statutory, advisory body/ गैर-वैधानिक, सलाहकार संस्था
- Tenure : constituted every three years/ हर तीन साल में गठित
- Headquarters : New Delhi

Advice



North Eastern Council (NEC)

- The North Eastern Council (NEC) is a statutory advisory body that plans and coordinates the economic and social development of the North Eastern Region (NER) of India./ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (NEC) एक कानूनी सलाह देने वाली संस्था है जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (NER) के आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाती है और उसे कोऑर्डिनेट करती है।

Establishment / स्थापना :

- Established on : 7th August 1972
- By : North Eastern Council Act, 1971/ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, 1971
- Type : Statutory Body/ कानूनी संस्था
- Headquarters : Shillong, Meghalaya
- 8 Member states : Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim (added in 2002)



North Eastern Council
Government of India

PRACTICE QUESTIONS



QUESTION : 01

→ full time → 5 Members

In which year was the National Human Rights Commission constituted in India?

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(a) 1995

(b) 2012

(c) 2002

(d) 1993

IRTED NTPC 2021





ANSWER : (d)

QUESTION : 02

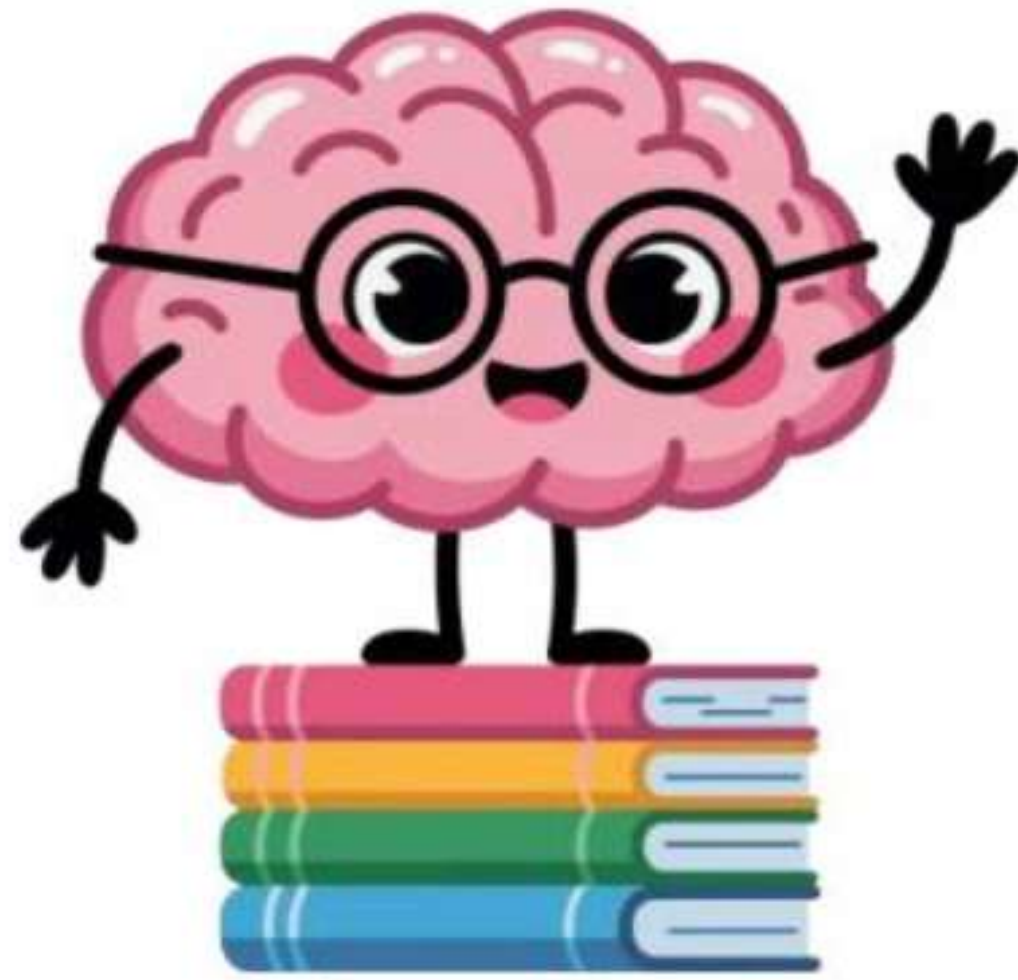
In India, National Human Rights Commission is under which of the following ministry?

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

- (a) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- (b) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- (c) Ministry of Defence / रक्षा मंत्रालय
- (d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

UPPSSSC PET 2022





ANSWER : (a)

QUESTION : 03

The Commission may, suo motu or on receipt of a petition, consider complaints on violation of human rights by the members of the Armed Forces.

आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर स्वयं संज्ञान लेकर या याचिका प्राप्त होने पर विचार कर सकता है।

(a) will check timely / समय पर जांच करेगा ✕

(b) Police attache concerned to investigate will be also to direct / संबंधित पुलिस को जांच के लिए निर्देश देगा ✕

(c) Will be able to ask for a report from the Central Government / केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा

(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

ANSWER : (c)



QUESTION : 04

What is the term of office of the Chairman and members of the National Human Rights Commission?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है?

- (a) 5 years or till the age of 70 years / 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
- (b) 3 years or till the age of up to 70 / 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
- (c) 5 years or till the age of 65 years / 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
- (d) 3 years or till the age of 65 years / 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

UPSC CAPF 2022





ANSWER : (b)

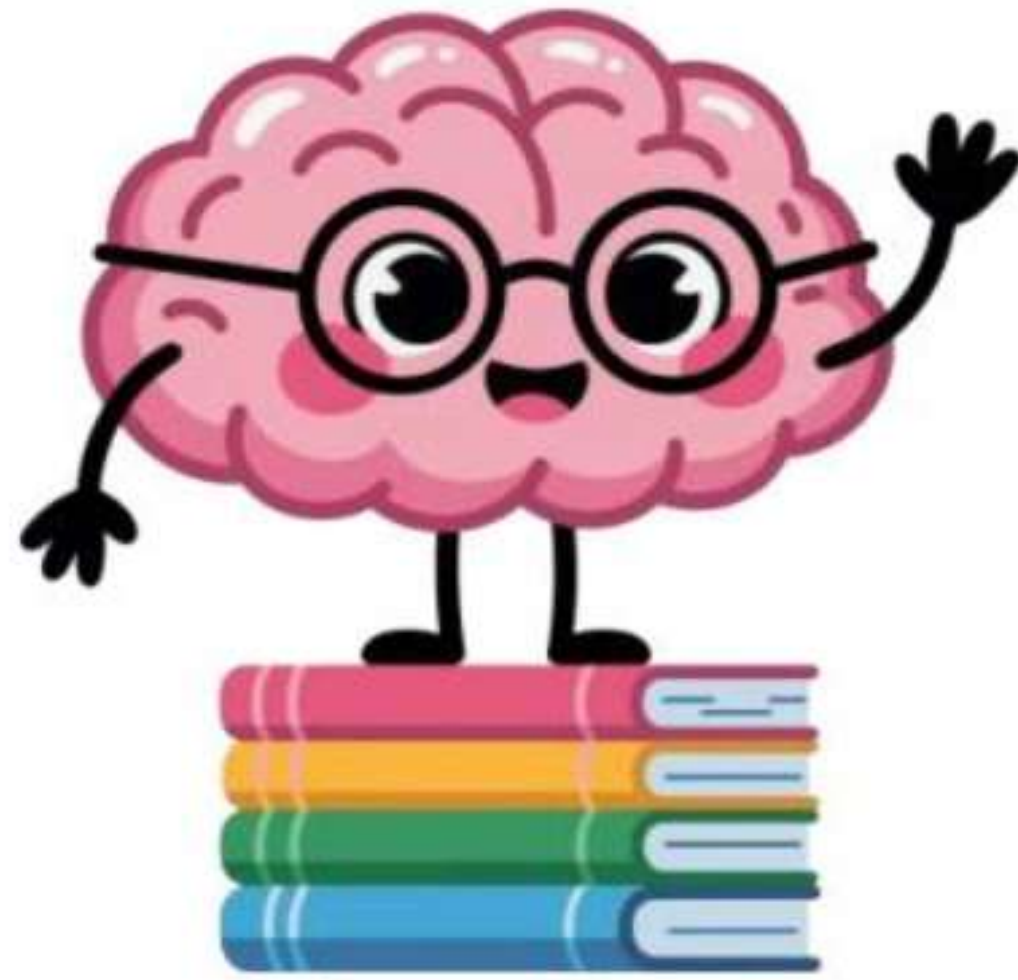
QUESTION : 05

Who among the following is not an ex-officio member of the National Human Rights Commission?

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है?

- ☒ (a) Chairperson of National Commission for Minorities / राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
- ☐ (b) Chairman of the Law Commission of India / भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष
- ☒ (c) Chairman of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
- ☒ (d) Chairperson of National Commission for Women / राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

MPPSC (Pre) 2018



ANSWER : (b)

QUESTION : 06

Which of the following is not an international human rights treaty?

निम्नलिखित में से कौन-सा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है?

- ☒ (a) International Covenant on Civil and Political Rights / नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध
- ☒ (b) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women / महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय
- ☒ (c) Convention on the Rights of Persons with Disability / विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय
- ☐ (d) Declaration on Right to Development / विकास के अधिकार पर घोषणा

ANSWER : (d)



QUESTION : 07

Who is not included in the committee recommending names for the appointment of Chairperson and members of the State Human Rights Commission?

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है?

(a) Chief Minister / मुख्यमंत्री ✓

(b) Speaker of the Legislative Assembly / विधानसभा अध्यक्ष ✓

(c) In-charge of the Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय के प्रभारी ✓

(d) Governor / राज्यपाल

MPPSC (Pre) 2021



ANSWER : (d)

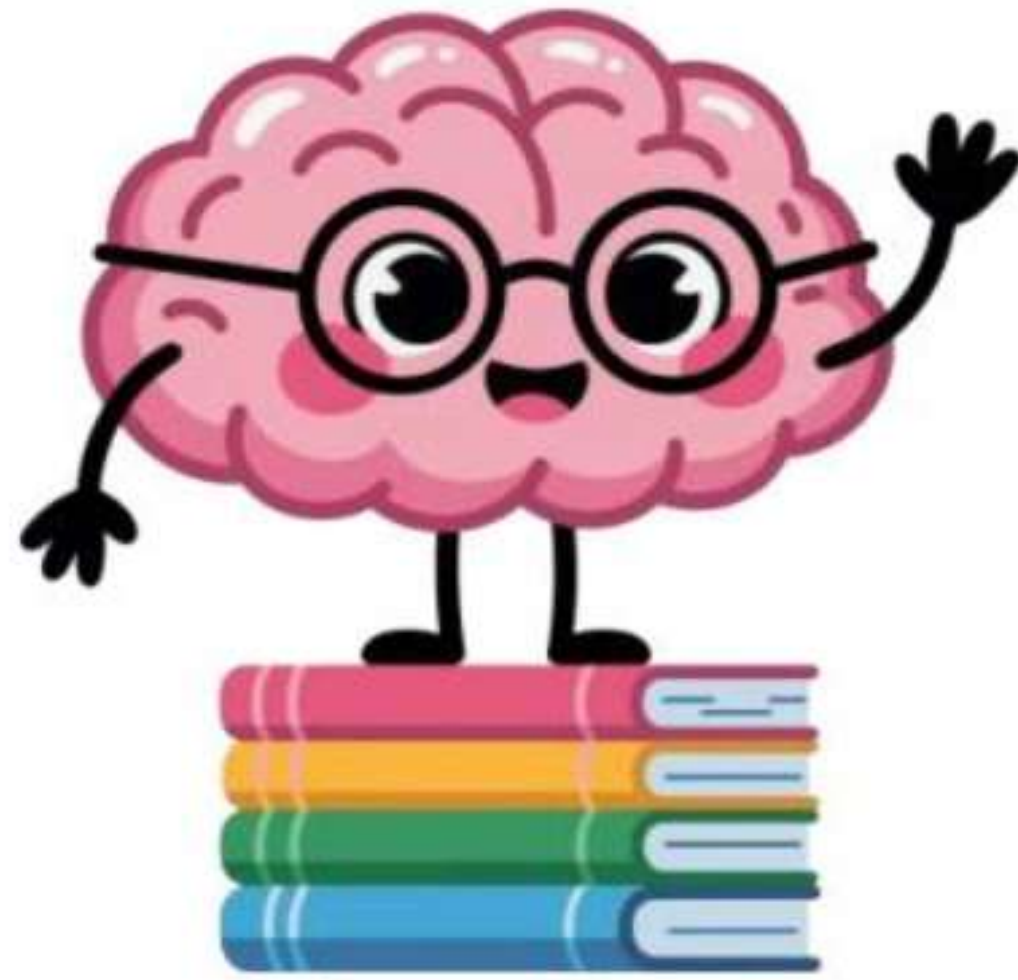
QUESTION : 08

Who chairs the committee constituted for the appointment of the members of the State Human Rights Commission?

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है?

- (a) Governor / राज्यपाल
- (b) Chief Minister / मुख्यमंत्री
- (c) Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश
- (d) Advocate General / महाधिवक्ता

MPPSC (Pre) 2023



ANSWER : (b)

QUESTION : 09

The National Commission for Women was established under which of the following Acts?

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी?

- (a) National Commission for Women Act, 1988 / राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1988
- (b) National Commission for Women Act, 1989 / राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1989
- (c) National Commission for Women Act, 1987 / राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1987
- (d) National Commission for Women Act, 1990 / राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

SSC CPO 2023



ANSWER : (d)



QUESTION : 10

Which of the following is not a Constitutional Commission in India?

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में संवैधानिक आयोग नहीं है?

- 338 (a) National Commission for Scheduled Castes / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 338 (b) National Commission for Backward Classes / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 338 (c) National Commission for Scheduled Tribes / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 338 (d) National Commission for Women / राष्ट्रीय महिला आयोग

UP RO/ARO (Pre) 2020



ANSWER : (d)

THANK
YOU

